



# राजस्थान रोजगार संधेध



(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 43 अंक 24

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

1 फरवरी, 2021

फोन : 2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु

## नागरिकों को रोजगार तथा उद्योगों / नियोजकों को जन-शक्ति उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार की अभिनव पहल

कोविड-19 की आपदा की घड़ी में श्रमिकों के पलायन व लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के बंद रहने से राज्य में अनेक वक्रे प्रस्तितियों के सामने रोजगार का तथा उद्योगों के समझे जन शक्ति की उपलब्धता का संकट आ गया था। ऐसे में जन-शक्ति व नियोजकों को एक मंच पर लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दिनांक 16 मई 2020 को मानवीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये गये निर्देशों की पाठना में मुख्य प्रौद्योगिकी एवं श्रम व रोजगार विभाग के समन्वयित प्रयत्नों द्वारा राजस्थान में उपलब्ध, सभी सेवा श्रेणियों की जन-शक्ति / श्रमिक व नियोजकों (Employers) का एक मास्टर डेटा-बेस "राज-कौशल" (Rajasthan Employment Exchange) मात्र 2 सप्ताह में तैयार किया गया। जिसका लोकार्पण

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून को किया गया था।

इसमें राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति (सैन्यांग श्रमिक, कोविड प्रवासी श्रमिक, पंजीकृत बेरोजगार, RSLDC प्रशिक्षित, ITI प्रशिक्षित इत्यादि) के डाटा को एक स्थान पर लाया गया है। साथ ही राज्य में उपलब्ध सभी संस्थान (उद्योग/व्यापार/प्रशिक्षण संस्थान) जो रोजगार देने में सक्षम है उनको BRN (Business Registration Number) या UAN (Udhog Aadhar Number) के आधार पर इस मास्टर डेटा-बेस में जोड़ा गया है।

श्रम सचिव श्रीमान नीरज के. मेवन् ने बताया कि इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रवासी लोगों को रोजगार दिलाने तथा उनका कौशल बढ़ाने के लिये की गयी राजस्थान सरकार की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा इससे प्रेरित होकर इस तरह के समाधान विकसित किये गए हैं / किये जा रहे हैं।

**राज-कौशल पोर्टल पर नागरिक/श्रमिक/जन-शक्ति अपने SSO ID, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के द्वारा उपलब्ध निम्न सेवाओं का सुगमता से लाभ ले सकते हैं:**

- पंजीयन।
- प्रोफाइल देखना, अपडेट करना तथा पंजीयन के आधार पर पोर्टल द्वारा बनाये गये बायोडाटा को डाउनलोड करना।
- नई सेवा/स्किल को जोड़ना।
- रोजगार की स्थिति अपडेट करना।
- अपनी सेवा की श्रेणी व कार्य के आधार पर उपलब्ध रोजगारों की तलाश करना।
- किसी उपलब्ध रोजगार के लिये आवेदन करना, ऐसा करने पर उसकी सूचना संबंधित नियोजका के पास उपलब्ध हो जाएगी।
- अपने आवेदनों की स्थिति जांचना।
- प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्ज कराना।

**राज-कौशल पोर्टल के माध्यम से नियोजका (उद्योग/ व्यापार/ प्रशिक्षण संस्थान/ ठेकेदार) BRN नंबर द्वारा अपनी वैधता सत्यापित कर, सुगमता से निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं:-**

- अपने संस्थान में रोजगार की आवश्यकता (JOB) दर्ज करना।
- पोस्ट किये गये JOB के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों की जानकारी देखना।
- नियोजका द्वारा रूचि दर्शाने पर आवेदनकर्ता से नियोजका की सूचना साझा की जायेगी।
- दर्ज आवश्यकता (JOB) के आधार पर उपलब्ध श्रमिक/जन-शक्ति उसे visible हो जाएगी। उसमें से किसी का भी प्रोफाइल देखकर नियोजका उसे SMS भेज पाएगा।
- उपलब्ध श्रमिक/जन-शक्ति में से नियोजका अपनी आवश्यकता (सेवा की श्रेणी, कार्य का प्रकार, पता इत्यादि) के आधार पर तलाश कर सकता है, तथा किसी भी नियोजका के प्रोफाइल में SMS भेजकर अपनी रूचि दर्शा सकता है।
- दर्ज आवश्यकता के विरुद्ध श्रमिक/जन-शक्ति से प्राप्त रूचि अथवा स्वयं द्वारा दर्शायी गयी रूचि के आधार पर यदि किसी श्रमिक/जन-शक्ति का नियोजका द्वारा चयन किया जाता है तो यह सूचना नियोजका को अपडेट करनी होगी।

इसके अलावा नियोजका अपना प्रोफाइल देखने, अपडेट करने का कार्य कर सकता है।

**सरकारी अधिकारियों हेतु पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं:**

राज-कौशल पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकारी उपयोगकर्ताओं हेतु SSO के माध्यम से लॉग इन कर डैशबोर्ड देखने, प्रवासी लोगों के कौशल की मैपिंग करने की सुविधा दी गयी है। जिस पर विभिन्न विभागों (यथाश्रम, रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, RSLDC, उद्योग इत्यादि) के जिला व उपखंड स्तर के अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

साथ ही विभिन्न विभागों यथा रोजगार, श्रम, उद्योग, RSLDC इत्यादि के जिलास्तरीय अधिकारियों को इस पोर्टल पर उपलब्ध रोजगार, श्रमिक, नियोजकों इत्यादि की सूचनाएं Excel फाइल में डाउनलोड करने तथा रोजगार प्रदान किये जाने की सूचना दर्ज करने का विकल्प दिया गया है।



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत "राज-कौशल" पोर्टल का लोकार्पण करते हुए।

**राजकौशल की सुविधाओं को कैसे access किया जा सकता है ?**

- [rajkaushal.rajasthan.gov.in](http://rajkaushal.rajasthan.gov.in) पोर्टल द्वारा
- [sso.rajasthan.gov.in](http://sso.rajasthan.gov.in) पर सिटीजन एप्लीकेशन में राजकौशल एप्लीकेशन द्वारा
- Google play store पर उपलब्ध राजकौशल मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा
- राजकौशल पोर्टल पर राजबोट (चेटबोट) की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसका उपयोग करके श्रमिक/नागरिक कुछ सामान्य प्रश्नों का हिंदी में जबब देकर अपना पंजीयन करवा सकता है। यदि पहले से पंजीकृत है तो अपनी प्रोफाइल (रोजगार की स्थिति, प्रशिक्षण की आवश्यकता, स्किल का विवरण) को अपडेट कर सकता है।

**वर्तमान स्थिति :-**

- कुल उपलब्ध श्रमिक/जन-शक्ति : 55.56 लाख
- श्रमिक/जन-शक्ति पंजीयन (स्वयं) : 42495
- श्रमिक/जन-शक्ति पंजीयन (प्रशासन द्वारा) : 173403
- कुल उपलब्ध नियोजका (Employers) : 11.18 लाख
- नियोजका (Employer) पंजीयन और प्रोफाइल अपडेट : 221
- कुल कौशल मैपिंग : 28.28 लाख
- प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग : 2.39 लाख
- कुल दर्ज रोजगार /आवश्यकताएँ : 30066
- प्रदान किये गए रोजगार : 1871
- नियोजका (Employer) पंजीयन और प्रोफाइल अपडेट : 221
- रूचि दर्शाने वाली जनशक्ति : 2650 (75 नियोजताओं में)
- रूचि दर्शाने वाले नियोजका : 1111

**भविष्य में राजकौशल एप्लीकेशन के माध्यम से रोजगार सम्बंधित निम्न सेवाएँ भी प्रदान की जानी प्रस्तावित है :-**

- प्लेसमेंट एजेंसी मॉड्यूल
- नागरिकों के लिए स्थानीय सेवाएं
- बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन हस्तांतरण
- कैरियर विकास और परामर्श सेवाएं
- शैक्षिक संस्थानों के लिए प्लेसमेंट सेल मॉड्यूल



रिक्तियों के लिए आवेदन दिया है, को केवल उसी पे मैट्रिक्स लेवल के अंतर्गत भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है, ऐसे मामलों में खिलाड़ियों को यह वृत्तबन्ध निश्चित कर देना होगा कि वह रेलवे में ज्वाइन करने के बाद, रेलवे में भर्ती होना से पहले अंतिम की गई खेल उपलब्धियों के आधार पर रेलवे में शामिल होने के बाद उच्च वेतन स्तर के लिए दावा नहीं करेगा, भयम के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा, बयानित नहीं हुए उम्मीदवार के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही रेल प्रशासन किसी डाक सुपूर्दगी अथवा गलत सुपूर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, किसी भी रूप में इसका प्रचार-प्रसार करना उम्मीदवार को अव्ययता नहीं जाएगी.

(xv) ट्रायल्स के पूर्व, उम्मीदवारों की Identity एवं समस्त प्रमाण पत्रों की समिति द्वारा जांच की जाएगी। समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा ट्रायल्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा।

(xvi) कोई भी पद विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है.

(xvii) शासकीय अथवा पब्लिक सेक्टर में कार्यरत आवेदन अपने एम्प्लोयेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(xviii) खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं अपडेट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट [www.secr.indianrailways.gov.in](http://www.secr.indianrailways.gov.in) का अवलोकन करते रहें.

**7. किसे / कौसे आवेदन करें :**

उपरोक्त पदों के लिए भर्ती हेतु केवल ऑन लाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट में ([www.secr-indianrailways-gov-in](http://www.secr-indianrailways-gov-in) → Recruitment → RRC Bilaspur → Sports Quota 2020-21) लिंक पर 'How to Apply' में दिये गए निर्देशों का पालन करें। खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं अपडेट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उक्त वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें.

**8. अनुलग्नक को अपलोड किया जाना :**

ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुति करने के समय उम्मीदवार को चाहिए कि वे अपेक्षित दस्तावेजों जैसे जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्पोर्ट्स योग्यता आदि की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें तथा इसमें अपि प्रमाणपत्र (अनुलग्नक ए) तथा अपि घोषणा पत्र (अनुलग्नक बी), अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक सी) अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय घोषणापत्र (अनुलग्नक डी) ईवीसी प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त (अनुलग्नक ई), वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21) के दौरान अर्जित विभिन्न स्तरों के खेलकूद उपलब्धियों के प्रमाणपत्र, उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो एक हस्ताक्षर शामिल है.

नोट- 1. आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं स्पोर्ट्स संबंधी सर्टिफिकेट जो आवेदन फार्म के साथ लगाए जायेंगे, केवल वे ही सर्टिफिकेट भर्ती हेतु विचार किए जाएंगे। बाद में कोई भी सर्टिफिकेट जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

2. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए। यदि Blur (धुंधले) सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं तो आवेदन अमान्य कर दिये जाएंगे।

**9. अमान्य आवेदन:**

निम्नलिखित में से कोई भी कतिमा / विसंगति / अनियमितता होने पर आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा:

- उचित तरीके से स्कैन किए गए फोटोकॉपी और हस्ताक्षर के बिना आवेदन। (फोटो रयान फोटो नहीं, साइड पोस्टर वाली फोटो नहीं, या पूरा का चरमा या टोपी नहीं।) फोटो स्कैन प्रकृति में और 80 % बेहरे के साथ होना चाहिए.
- निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धियों, जाति प्रमाण पत्र (अपि / अजा / अपिब घोषणा) के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन, (उम्मीदवारों के पास अधिसूचना की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शिक्षा और खेल उपलब्धियाँ होनी चाहिए।)
- एक इवेंट के लिए एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन.
- हाथ से भेजे गए आवेदन, (ऑनलाइन जमा नहीं किया गया).
- कोई अन्य कथित अनियमितता.
- उचित फीस के बिना आवेदन.
- स्पष्ट सर्टिफिकेट के बिना आवेदन.

अधिसूचना में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना मान्य होगी.

सहायक कार्यालय अधिकारी (भर्ती)  
कृते प्रधान मुख्य कार्यालय अधिकारी

**ANNEXURE -"A"**

**OBC CERTIFICATE FORMAT**

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is certified that Shri/Smt./Kumari ..... Son/Daughter of ..... of Village/Town ..... in District/ Division ..... in the State/Union Territory ..... belong to the ..... community which is recognized as Backward Class by the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. .... dated .....

Shri/Smt./Kumari ..... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ..... District/Division of the ..... State union Territory. This is also to certify that he/she/ does not belong to the person/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Est.(SCT) dated 08.09.1993 and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017\*\*

Date: \_\_\_\_\_

**DISTRICT MAGISTRATE / DY. COMMISSIONER ETC.**

\* The authority issuing the certificate may have to mention the detail of resolution of Government of India, in which the caste of the candidates is mentioned as OBC  
\* As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**ANNEXURE -"B"**

**DECLARATION**

Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates at the time of practical demonstration and document verification, who had applied for the post against

Employment Notification No. .... (Sports Quota for the year 2020-21)

"I, ..... son/daughter of Shri ..... resident of village/town/city ..... District ..... State ..... hereby declare that I belong to the ..... (indicate your sub caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Est.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.03.1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of the Candidate  
Place: \_\_\_\_\_ Name of the Candidate

**FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST**

This is to certify that Shri/ Smt/ Kumari ..... son/daughter\* of ..... Village/Town ..... District/Division\* ..... of the of State/Union Territory\* ..... belongs to the ..... Caste\*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* under-

- \*The Constitution (Scheduled Caste) order, 1950.
- \*The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950.
- \*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) (Part C States) order, 1951;
- \*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) order, 1951;
- \*[As amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Lists (Modification), Order, 1956 the Bombay Re-organization Act 1960, the Punjab Re-organization Act, 1956, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Re-organization) Act, 1971, and the Scheduled caste and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1978].
- \*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Orders, 1956.
- \*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.
- \*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
- \*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
- \*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
- \*The Constitution (Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967.
- \*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
- \*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
- \*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
- \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978.
- \*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
- \*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Orders, 1989.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990.
- \*The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
- \*The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
- \*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
- \*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in case of Schedule Caste/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt.\* ..... father/mother\* of Shri/Smt./Kumari ..... of Village/Town\* ..... of the State/Union Territory\* ..... who belongs to the ..... Caste\*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/ Union Territory\* issued by the ..... dated .....

3. Shri/Smt./Kumari\* ..... and/or\* his/her\* family ordinarily resides in Village/Town\* ..... District/ Division\* ..... of the State/ Union Territory\* of .....

Signature \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
(with seal of Office)  
State/Union Territory \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

\*Please delete the words which are not applicable.  
@ Please quote the specific presidential order.  
\*Delete the Paragraph, which is not applicable.

Note : The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate /City Magistrate / Sub- Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate) 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officers not below the rank of Tahsildar, 4. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his/ her family normally reside(s), 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned, 6. Administrator /Secretary to Administrator (Lakshadweep, Minicoy and Andaman Islands).

**घोषणा पत्र**

रोजगार अधिसूचना सं. .... (खेल कोटा) के लिए परीक्षा शुल्क में आर्थिक छूट हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा

मैं, ..... पुत्र /पुत्री श्री ..... ग्राम /शहर ..... जिला ..... राज्य .....

का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ..... का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ..... सहायक के अंतर्गत आता हूँ। (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / जोरास्ट्रियन (पारसियों) को इंगित करें।

दिनांक: ..... उम्मीदवार के हस्ताक्षर  
स्थान: ..... उम्मीदवार का नाम  
नोट: परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क की माफी का दावा करने के लिए नैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है (अर्थात् मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / जोरास्ट्रियन (पारसी)।

अनुलग्नक - ई\*

**ईवीसी के लिए आय प्रमाण पत्र**

रोजगार अधिसूचना सं. .... (खेल कोटा) के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा

1. उम्मीदवार का नाम: .....
2. पिता का नाम: .....
3. आय: .....
4. आवासीय पता: .....
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में): .....

दिनांक: ..... हस्ताक्षर: .....  
नाम: ..... जारीकर्ता प्राधिकरण की मुहर: .....  
नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/-रु. से कम है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण अधिकृत हैं:  
(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर का कोई अन्य राजस्व अधिकारी, (2) लोकसभा का वर्तमान सांसद सदस्य अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए (3) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इन्जुल्ट एम्प्लॉय (4) केंद्रीय गरीबी देश के किसी भी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष / आरआरसी को सिफारिश कर सकते हैं (5) राज्य सभा के वर्तमान सांसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिस जिले में वे सांसद रहते हैं।

72<sup>वां</sup>  
गणतंत्र  
दिवस

  
सत्यमेव जयते  
राजस्थान सरकार

 

#राजस्थान\_सतर्क\_है

विविधता में  
एकता की शान  
हमारा गणतंत्र  
हमारा अभिमान



विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलने वाले हमारे गणतंत्र पर हमें गर्व है।

आइये, इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेश के हर वर्ग के स्वास्थ्य की मंगलकामना करें।

कोरोना महामारी से बचाव के उपायों को अपनाते हुए आगे बढ़ें एवं प्रदेश की तरक्की में अपना हर संभव योगदान करने का संकल्प लें।

**समस्त प्रदेशवासियों को  
72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं..**

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री



- कोविड-19 टीकाकरण में भी राज्य को मॉडल बनायेंगे
- यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है
- अन्य गाईडलाइन्स आने तक पहले की तरह ही सावधानियां अपनायें

राजस्थान संवाद

# राष्ट्रभाषा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

राष्ट्रीय विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा की अत्यंत प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा द्वारा ही समाज की व्यवस्था में परिवर्तन और परिष्कार करने में सफलता मिलती है यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा से योग्य विद्यार्थी समाज के भावी नागरिक के रूप में तैयार किये जायें, ताकि वे समाज के स्तर को उठाने में सक्षम हों। इसके लिए बृहद एवं व्यावहारिक शिक्षा नीति होना आवश्यक है। शिक्षालयों में शिक्षा को उपयोगी बनाने वाली प्रविधियों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, जिससे छात्र शिक्षा के प्रति सचेत हो तथा अपनी शैक्षिक रुचियों एवं अभिवृत्तियों का विकास कर सकें।

इसके लिए सभी विद्यालयों में मातृभाषा शिक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाता है। जिससे शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित द्वि-भाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालकों को तीन भाषाएँ पढाई जाती हैं- **हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी**।

हिन्दी का शब्दिक अर्थ है हिन्द का और हिन्द शब्द बना है संस्कृत के सिंधु से - सिंधु-हिन्दु-हिन्द। संस्कृत का सिंधु फारसी में हिन्दु हो गया है। अतः मूलतः सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिन्दु कहा, उस भूभाग को हिन्द कहा और उनकी भाषा हिन्दी बतलाई।

अहिन्दी भाषा प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा द्वितीय भाषा के रूप में होती है। इसका उद्देश्य बालकों में भाषा कौशल को विकसित करना है। अर्थात् सुनकर समझना हिन्दी में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करना, हिन्दी में लिखित सामग्री को समझते हुए पढ़ना और हिन्दी में अपने विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करना।

राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा क्रम में इसे अनिवार्यता प्रदान की गई है।

## भाषा का महत्व:-

भाषा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा, विचार में सम्प्रेषण का माध्यम है। जिसकी सहायता से प्रयोजन की सिद्धि हेतु युक्त किया जाता है और वह प्रयोग के संदर्भ एवं परिस्थिति में अर्थग्राहण करता है।

**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाषा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है-** भाषा राष्ट्र के आकाश का पवन प्रवाह है जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करता बल्कि राष्ट्र के सौरभ को भी देश-विदेशों में प्रसारित करता है।

हमारे देश में जितनी भी भाषाएँ प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक गौरवपूर्ण स्थान हिन्दी को ही प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा में अब तक 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है। परन्तु प्रश्न यह उपलब्ध होता है कि किसी भाषा को बस भाषाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

भारतीयों, मनीषियों, विचारकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रीयता के उन्मूलकों ने अनेक विशेषताओं तथा सर्वाधिक राष्ट्रव्यापी जन भाषा के आधार पर हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव प्रदान किया और संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा को मान्यता मिली। अतः हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है **'हिन्दी'**।

राष्ट्रभाषा राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली, उसमें अस्मिताबोध जगाने वाली संजीवनी है।

स्वतंत्रता से पूर्व हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। स्वतंत्रता की चेतना जाग्रत करने के लिए समाज सुधारकों ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने में अपनी शक्ति लगाई जिससे स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया हिन्दी पाठ्यक्रम में समाहित अन्य विषयों की भांति एक विषय ही नहीं है बल्कि सभी विषयों के ज्ञानार्जन और शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम भी है।

हमारे देश में शिक्षा मुख्यतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यम की दृष्टि से

हिन्दी भाषा का अधिक महत्त्व नहीं रहता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों में निरंतर इस भावना की वृद्धि हो रही है। वहाँ भी केवल हिन्दी विषयों की शिक्षा हिन्दी माध्यम से होती है, शेष विषयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

इस समस्या को देखते हुए **कोठारी कमीशन रिपोर्ट (1964-66)** पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केरल सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर मांग की थी कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा का अध्ययन **'पुस्तकालयी भाषा'** के रूप में तो अवश्य किया जाए पर अंग्रेजी या अन्य किसी भी विदेशी भाषा को माध्यम ना बनाया जाए शिक्षा के माध्यम के रूप में सारे देश में हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

हिन्दी पूरे देश की सम्पर्क भाषा है और इस रूप में इसकी अनेक शैलियाँ हैं। यह केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में काम-काज की भाषा भी है।

**पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था - हिन्दी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्र भाषा बनने की योग्यता रखती है।**

हिन्दी मातृभाषा तो है ही, भारत की राष्ट्रवाणी भी है, ऐसी वाणी जो राष्ट्र की आत्मा, व्यक्ति और उसे विचारों तथा सरकारों की प्रवाहिका है। हिन्दी के वट वृक्ष ने अपनी शीतल छाया अन्य भाषाओं को प्रदान की है।

राष्ट्रवाणी हिन्दी गुरुनानक, अमीर खुसरो, जायसी रहीम, रसखान की भी भाषा है। हिन्दी किसी धर्म विशेष सम्प्रदाय की भाषा नहीं है यह समस्त भारत की भाषा है।

माध्यमिक कक्षा का चयन इसलिए किया गया है कि विद्यार्थी अपनी आयु एवं योग्यता के आधार पर हिन्दी भाषा के प्रति अपनी अभिवृत्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें और इस स्तर तक आकर ही छात्र-छात्राओं में भाषा कौशल, मुना, बोलना, पढ़ना-लिखना आदि का सही विकास होता है तथा अभिवृत्तियों एवं रुचियों का भी विकास संभव हो पाता है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में बाह्य तथ्य, वस्तुओं, विचारों तथा घटनाओं के प्रति कुछ निश्चित धारणाएँ विकसित कर लेता है इन धारणाओं के कारण ही व्यक्ति किसी को पसन्द करते हैं तो किसी को देखकर खुशी से झूम उठते हैं तो किसी को देखकर घृणा से मुँह सिकोड़ लेते हैं।

**वर्स्टन के अनुसार - 'कुछ मनोवैज्ञानिक पथों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी है।'**

अभिवृत्तियों से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति संस्था, वस्तु या प्रक्रिया के प्रति अनुकूल एवं प्रतिकूल सकारात्मक एवं नकारात्मक विचारों को व्यक्त करने से है।

**फ्रीमैन के अनुसार -** अभिवृत्ति किसी निश्चित परिस्थितियों में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप में प्रयुक्त देने वाली यह स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष के प्रयुक्त देने की लाक्षणिक शैली बन जाती है।

अभिवृत्ति मापनी में कथनों को मात्राओं के अंतर से प्रस्तुत किया जाता है तथा इस प्रकार उस व्यक्ति की उन कथनों के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात किया जाता है।

अभिवृत्ति किसी वस्तु या प्रक्रिया के प्रति व्यक्ति की स्वाभाविक तत्परता है। इसका स्वरूप स्थायी एवं एक रूप होता है। यह सदैव परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति की विशिष्ट दिशा को निर्देशित करती है।

किसी व्यक्ति - वस्तु संबंध की ओर संकेत करती है। प्रायः भाव एवं संवेगों से सम्बंधित होती है। यह अनुभवों के आधार पर अर्जित की जाती है तथा वस्तुओं, मूल्यों एवं व्यक्तियों के सम्बंध से सीखी जाती है। इनके विकास में प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक तत्त्व सहायक होते हैं। ये सामान्य रूप (वर्ग के प्रति) एवं विशिष्ट (व्यक्ति के प्रति) दोनों ही प्रकार की होती है। इनका सम्बंध व्यक्तित्व के वृहत् पक्षों बुद्धि, मानसिक, प्रतिभा एवं शब्दिक विचारों से होता है।

ये व्यवहार को प्रभावित करती है अतः एक एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का दूसरे व्यक्ति की अभिवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है इसलिए ये व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अंकन करने में भी सहायक होती है।

कोई भी विषय जब पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर रखा जाता है परन्तु हिन्दी का विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ भारत में बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा भी है। अतः इसका अध्ययन-अध्यापन करने-कराने के साथ-साथ यह देखना भी आवश्यक है विद्यार्थी हिन्दी ने विषय को कितना और किस रूप में इसका प्रस्तुतीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे।

विषय को विद्यार्थियों को पढ़ाने समय यह भी ज्ञात करना आवश्यक है कि इसके प्रति विद्यार्थियों का क्या दृष्टिकोण है, वे इसमें कितनी रुचि से पढ़ते हैं या फिर मात्र परीक्षा में पास होने के लिए ही पढ़ना आवश्यक समझते हैं।

राष्ट्रभाषा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में अलग-अलग प्रकार से पाई जाती है। राष्ट्रभाषा के प्रति इन विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में भी अंतर है।

हिन्दी हमारी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है। हिन्दी सम्पर्क भाषा है। जो न्याय की भाषा भी है, प्रादेशिक भाषा है। अतः शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिये। हिन्दी भारतीय संस्कृति की भाषा है।

हिन्दी असानी से बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा से कुछ तकनीकी विषयों की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

## हिन्दी भाषा से विनम्रता आती है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने से प्रादेशिकता की भावना बढेगी। हिन्दी विज्ञान की भाषा है। हिन्दी सुसंस्कृत भाषा नहीं है बल्कि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा है।

## 'हिन्दी' फिर्सी मनोरंजन की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है।

हिन्दी वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के ज्ञान में सहायक नहीं है। संविधान में सभी भाषाओं का समान महत्त्व है। हिन्दी भाषा में सर्वाधिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं।

## भाव प्रकट करने का सरलतम साधन है, हिन्दी।

हिन्दी तकनीकी भाषा है। विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्ति पाई जाती है। बालकों में विषय की ग्राह्यता को विकसित करने के लिए समय-समय पर हिन्दी विद्वानों, साहित्यकारों के भाषणों, टेप किट्ट हूप कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विचार गोष्ठियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठियाँ आदि की भी व्यवस्था करवाई जानी चाहिये।

प्रज्ञा शर्मा  
शोधकर्ता



खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी, कोरापुट-763 008, ओडिशा, भारत  
(CIN: L27203OR1981GOI00920)  
एक नवरत्न कंपनी

## खनन मित्र / फोरमैन खनन की भर्ती

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), एक नवरत्न कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संकुल है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी है, जिसकी वर्तमान में कुल आय लगभग रु. 8426 करोड़ है। कंपनी भारत एवं विश्व भर में अत्यधिक विकास एवं विचार के लिए अग्रसर है। कंपनी को निर्यात के क्षेत्र में प्रीमियर ट्रेडिंग हब्स का दर्जा भी प्राप्त है जिसने अपने हितधारकों के महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कंपनी का निगम कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा होने के साथ संबंध और कार्यालय बहू-स्थानीय हैं। कंपनी सक्षम मानव संसाधनों और "लोक केंद्रित" दृष्टिकोण वाले अभ्यासों के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में विज्ञान करती है।

धातु और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, खान एवं परिशोधन संकुल, नलको, दामनजोड़ी, निम्नलिखित अनुशासन और पद के लिए प्रतिबद्ध, हेनलर और परिणाम-उन्मुख अभ्यर्थियों को तलाश में है:

### ए. पदों का विस्तार विवरण:

क्र. सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	अपेक्षित योग्यता	अनुभव (वर्ष में)	प्रेरण स्तर	अधिकतम आय सीमा (वर्ष में)
01	खनन मित्र	18 (अ.जा.-3, अ.पि.व.-4, आ.क.व.-1, अना.-10)	अभ्यर्थी के पास आवश्यकता है, जिसकी वर्तमान में कुल आय लगभग रु. 8426 करोड़ है। कंपनी भारत एवं विश्व भर में अत्यधिक विकास एवं विचार के लिए अग्रसर है। कंपनी को निर्यात के क्षेत्र में प्रीमियर ट्रेडिंग हब्स का दर्जा भी प्राप्त है जिसने अपने हितधारकों के महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कंपनी का निगम कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा होने के साथ संबंध और कार्यालय बहू-स्थानीय हैं। कंपनी सक्षम मानव संसाधनों और "लोक केंद्रित" दृष्टिकोण वाले अभ्यासों के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में विज्ञान करती है।	अनुभव की आवश्यकता नहीं	श्रेणी 0 से पूर्व	27 वर्ष
				2 वर्ष	श्रेणी 0	35 वर्ष
				5 वर्ष	श्रेणी 1	38 वर्ष
				8 वर्ष	श्रेणी 2	41 वर्ष
02	फोरमैन खनन	08 (अ.जा.-1, अ.पि.व.-2, अना.-5)	अभ्यर्थियों को डिप्लोमा इन मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होना चाहिए और डिप्लोमा इन खनन फोरमैन द्वारा प्रमाणपत्र भी होना चाहिए	अनुभव की आवश्यकता नहीं	एस 0 से पूर्व	28 वर्ष
				2 वर्ष	एस 0	40 वर्ष
				5 वर्ष	एस 1	43 वर्ष
				8 वर्ष	एस 2	46 वर्ष

### बी. महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- उपरोक्त उपरोक्त की गई संक्षिप्तता अ.जा. (अनुसूचित जाति), अ.पि.व. (अन्य पिछड़ा वर्ग), आ.क.व. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), अना. (अनारक्षित), अ.जा. (अनुसूचित जाति), यू.पू.से. (भूत पूर्व सैनिक) के लिए है।
- योग्यता केंद्रीय / राज्य सरकार (जहाँ भी लागू हो) द्वारा स्थापित न्यूनतम / एआईसीडीई / एनसीडीवीटी / एससीडीई और सीटी जैसे निकटवर्ती / संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों से होनी चाहिए। केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। इसमें न्यूनतम आवश्यक योग्यता, कॉलेज के तहत मैट्रिक / समकक्ष शामिल होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उन्नत उद्घाटन निर्धारित अर्हता, अनुभव, आयु इत्यादि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अपना उम्र से पहले प्राप्त नहीं की है, आवेदन न करें।
- अभ्यर्थियों के पास वैध रोजगार विनियम पंजीकरण काई होना चाहिए।

### सी. परिलिखित एवं अन्य लाभ

जहाँ तक कंपनी लागत (कॉस्ट टू कंपनी) की बात है, कंपनी विकास पर केंद्रित एक पेशेवर प्रबंधित संस्थान है जिसमें योग्यता-उन्मुख उन्नति के अवसर के साथ कंपनी धन और सुविधाओं के रूप में एक शानदार पैकेज प्रदान करती है:

- एसयूपीटी (जेओटी) पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी:
  - निकल अपरेटेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (जेओटी/एसओटी) पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग से मुक्तता होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें प्रतिमाह 12000/- का वजीफा दिया जाएगा।
  - एसयूपीटी के एक वर्ष के सफल समापन के बाद, ऑनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (जेओटी) / सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (एसओटी) को 18 महीने की अवधि के लिए शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीने के लिए रु. 15000/- प्रतिमाह और शेष 6 माह के प्रशिक्षण के लिए रु. 15500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।
  - प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (कंपनी के अंदर व बाहर) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
  - सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें 0 ट्रेड में नियमित रोजगार में स्थान के लिए रु. 29500-3%-70000/- के वेतनमान के साथ-साथ नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलिखित के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा।
  - कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।
- एसयूपीटी (एसओटी) पद के लिए चयनित उम्मीदवार:
  - निकल अपरेटेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (एसओटी) के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए,

- ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से मुक्तता होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें प्रतिमाह 12000/- का वजीफा दिया जाएगा।
- एसयूपीटी के एक वर्ष के सफल समापन के बाद, 18 महीने की अवधि के लिए सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (एसओटी) को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीने के लिए रु. 16000/- प्रतिमाह और शेष 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए रु. 16500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (कंपनी के अंदर व बाहर) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें एस 0 श्रेणी में 36500-3%-115000/- वेतनमान के साथ नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलिखित के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा।
- कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।

### ❖ एसयूपीटी (जेओटी) / एसयूपीटी (एसओटी) के अलावा अन्य पद के लिए चुने गए उम्मीदवार

एसयूपीटी (जेओटी) / एसयूपीटी (एसओटी) के अलावा अन्य पदों के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमानुसार नियमित कर्मचारियों के रूप में मिलने वाले लाभ जैसे कि छुट्टी, कैन्टीन भत्ता, राशि भत्ता, प्रोत्साहन, परिवहन खर्च, कंपनी आवस्य व मकान किराया भत्ता, जीआईएस, अंशदायी भविष्य निधि और उपवन के साथ निम्नलिखित श्रेणी और वेतनमान में रखा जाएगा:

पदनाम	श्रेणी	वेतन मान
खनन मित्र श्रेणी III	श्रेणी 0	रु. 29500-3%-70000/-
खनन मित्र श्रेणी II	श्रेणी 1	रु. 31500-3%-80000/-
खनन मित्र श्रेणी I	श्रेणी 2	रु. 34000-3%-90000/-
कनिष्ठ फोरमैन (खनन)	एस 0	रु. 36500-3%-115000/-
सहायक फोरमैन (खनन)	एस 1	रु. 37200-3%-120000/-
फोरमैन (खनन)	एस 2	रु. 37900-3%-125000/-

### डी. चयन प्रक्रिया

- इस विज्ञापन में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एक संक्षिप्त सूची (शॉर्टलिस्ट) किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों के चयन का आधार लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, संगठनात्मक आवश्यकता, पद्युत्पादन व आरक्षण के नियमानुसार किया जाएगा।
- विज्ञापन में दिए निर्देशों को पूरा करने से एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए, यह जरूरी नहीं है। मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थियों को संख्या को सीमित करने के लिए योग्यता और / या अनुभव के मापक को ध्यान में रखकर प्रश्न न्यूनता पराता मानकों / मानदंड नहीं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

### ई. चिकित्सा योग्यता

कंपनी में अभ्यर्थी का अंतिम पर्यन, जिस पद के लिए उम्मीदवार चुना है, कंपनी के चिकित्सा अधिकारी/ डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच के लिए जहाँ कंपनी का कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है, वहाँ एक अनुमोदित सरकारी अस्पताल/मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। कंपनी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

### एफ. स्थान

परीक्षा अवधि के दौरान और/ या समाप्ति के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को नालको में, भारत या विदेश या कहीं भी सहायक / संयुक्त उपक्रम/नालको के व्यावसायिक सहयोगियों में स्थान व संस्थान की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनके क्षेत्र से संबंधित सेवा / कार्य / जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसमें शिफ्ट आंदोलन भी शामिल है।

### जी. आरक्षण एवं सूट

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-श्रीमती लेबर) / अकाव/ दिव्यांग/विकलांगता की डिग्री 40% या अधिक का भूतपूर्व-सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण/सूट, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होता है। कुल पदों की संख्या में यदि या कमी के मामले में, आरक्षित श्रेणी के पदों की संख्या सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग होती।
- दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए आरक्षण प्रवर्धित नियमों के अनुसार शैक्षणिक आधार पर होगा। यदि ईएसएम के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपयुक्त ईएसएम अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो ईएसएम के अलावा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी पदों को भरा जाएगा।
- आकाव श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे यूआर श्रेणी के लिए निर्धारित पाठ्य मानदंडों को पूरा करते हों।
- दिव्यांग के लिए लागू आरक्षण / रियायतों के लाभ का दावा करने के लिए, अभ्यर्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 591 (ई) दिनांक 15.06.2017, दिव्यांग नियम, 2017 के नियमों के अध्याय - VII (नियम -17 से नियम -20) के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अभ्यर्थियों को इस उद्देश्य के लिए दिव्यांग के लिए विशेष रोखाव विनियम से संलग्न चिकित्सा बोर्ड अलावा सरकारी अस्पताल के 3 चिकित्सकों के पैनल द्वारा असाधारित व मोहर लगा वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कार्य, स्थान आदि के कार्टेजों और जिम्मेदारियों को प्रकृति पर विचार करने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुछ रिक्तियों की विनिर्दिष्ट की पेशकश की जाएगी और यह भी विचार किया जाएगा कि उनकी आरक्षणित उनके प्रदर्शन के आधे नहीं हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या को भी नुकसान न पहुंचे। यद्यपि अंतिम विनिर्दिष्ट और स्थान अभ्यर्थी के द्वारा उस विनिर्दिष्ट के संबंध में चिकित्सा योग्यता के आधार पर किया जाएगा विसर्ग के लिए उम्मीदवार चुना है।
- अजा/ अजमा / अर्धव्यंग/ भूतपूर्व सैनिक / आकाव की श्रेणी एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने के बाद नहीं बदला जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- यदि अजा/ अजमा / अर्धव्यंग/ दिव्यांग/ पूर्व सैनिक / आकाव प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी के अलावा अन्य भाषा में जारी किए गए हैं, तो अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक को स्व-प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
- अपने अभ्यर्थी को "श्रीमती लेबर" से संबंधित है, अपेक्षित श्रेणी के लिए स्वीकार्य रियायत के इच्छावर्त नहीं है और ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को अनारक्षित (यूआर) के रूप में हीन करना होगा। अपेक्षित (गैर-श्रीमती लेबर) अभ्यर्थियों को श्रीमती लेबर वर्ग में जारी एक सक्षम अधिकृत से भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में अपेक्षित (गैर-श्रीमती लेबर) प्रमाण पत्र में हीनता जाति और समुदाय का नाम दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा, अपेक्षित अभ्यर्थियों को यह कतबे हुए एक स्व-अभिव्यक्त देना होगा कि वे लिखित परीक्षा के समय अपेक्षित (गैर-श्रीमती लेबर) श्रेणी के हैं, यदि उन्हें बुलाया जाता है।
- आकाव अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित आय और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- अजा/ अजमा के लिए उम्मीदवार आयु सीमा में 5 वर्ष, अपेक्षित (गैर-श्रीमती लेबर) के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अनारक्षित (अजा) के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अपेक्षित (गैर-श्रीमती लेबर) के लिए 13 वर्ष की छूट दी गई है और पीडब्ल्यूडी-अजा/ अजमा (क्रमशः)





#राजस्थान\_सतर्क\_है

## निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

प्रिय प्रदेशवासियो,

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही 'पहला सुख निरोगी काया' हमारे लिए सर्वोच्च सरोकारों में से एक है। इसी ध्येय से पहले हमने निःशुल्क दवा योजना तथा निःशुल्क जाँच योजना शुरू की थी, जो आज भी देश में मिसाल बनी हुई हैं। इसी प्रतिबद्धता के तहत हमने दिसम्बर 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान लागू किया। गत 10 महीनों से शानदार कोरोना प्रबंधन किया तथा कोरोना टीकाकरण में भी राज्य को मॉडल बनाएंगे। अब हम 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू कर रहे हैं। यह एक ऐसी अभिनव पहल है जो प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपये का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपये) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। सरकारी के साथ-साथ सार्वजनिक निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। खास बात है कि भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल किया गया है। राजस्थान की इस अभिनव योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और जीवन रक्षा के इस मिशन में भागीदार बनें।

शुभकामनाओं सहित,

(अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री)

राजस्थान की एक और अभिनव पहल जो बनेगी मिसाल

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

नवीन चरण का शुभारंभ : 30 जनवरी, 2021

इलाज के लिए अपना जन-आधार या आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाएं

संपर्क करें : 1800 180 6127 या 181 | [www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby](http://www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby)

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित

रा.सं.सं 04/2021

### वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

### सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

### राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक  
महेश शर्मा  
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशक  
राजस्थान, जयपुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक  
हरी राम बड़गुजर

सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,  
आक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,  
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398

ई-मेल: [adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in](mailto:adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in)